EDITORIAL

Post VRS - Revival of BSNL

After ups and down for a long span of time, a revival plan was approved by the union cabinet on 22.10.2019 based on IIM Ahmadabad recommendation. Though the DOT ignored Several recommendations of IIM which were beneficial to workers. The plan was approved including VRS of staff and it was implemented in name of BSNL VRS 2019. The window for VRS Was opened for one month i.e. 4th Nov. 2019 to 3rd December 2019. Total 78569 employees executive and non-executives opted for VRS under a compelling situation created by the management and other vested interest group within the campus of company. The threatening of CMD in his speech on 25th October 2019 at corporate office created fear and confused the entire work force of BSNL. Taking the idea from the speech of CMD the top level officers at circle/BAI SSA repeatedly spreaded the same version which created a havoc among the workers and large number of employees made their mind to left the company and opted for VRS.

At initial stage it was told that the VRS process will be completed very smoothly and the optees will sent on retirement with happiness but the seen at ground level is totally different from what was told by the Top management continuously.

Two types of orders were issued for vigilance clearance and the grey area off pensionary benefits were not clarified even after several communications made by the NFTE. Neither DOT nor the Hon. Minister considered to remove the doubts of the union which will create a big problem to retires on VRS.

Example of happy retirement is cited by the management by stopping payment of Rs. 3001 as token of honorarium on retirement and all the optees of VRS were insulted by adding that the flower bouquet and refreshment will not be given to retiree. NFTE lodged a protest against it but no review was done even after the interference of Director (HR). The episode of retirement on VRS of a large number of employees will be completed on 31st January 2020 without payment of even salary for the month of December 2019 and January 2020.

Now what will be the Post VRS scenario in BSNL. What steps the management is going to take in course of revival of BSNL. The land monetization, issue of sovereign guaranteed bond and rolling out the 4G spectrum, all this part of plan are still in dilema. How the services will be maintained from 1st February 2020 onward, nothing is clear. Policy of outsourcing has been adopted and some guidelines for it has been circulated but at field level vested interested groups are not adopting a transparent process of out Scorning **Search committee acting with some other angle which smell fishy.** NFTE suggested the management to continue the services of those employees who were expert to maintain services of OFC, Broadband, leased lines, for a month or two or till finalisation of other system, but it was ,ignored by the management. It is apprehended that very early from 1st Feb. 2020 our services will badly detoriated and the private Telecos may try to snatch our customers. There is lac of proper planning, imagination, understanding, proper decision and effective execution

The non-optees are also living in fear as there is no proper norms and guideline, for future. In some places exploitation through transfer has started and a new industry is opened for cancellation of transfer and change of station of posting.

The future of non-optees looks dark for which all unions and Associations should come forward again and the unity which stopped several anti workers policy of the Govt. may be brought again for safeguard of the employees who are continuing their service in BSNL. At present scenario the number of observed employees be less than the BSNL recruits, who are having the long length of service. They should rally to unite, otherwise future of these employees may be a question mark?

The NFTE (BSNL) being a vanguard and safe-net of the working class from very long span of time is still ready to join with all unions to built up unity to save the BSNL and its employees.

संपादकीय

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत बीएसएनएल का पुनरूत्थान

लंबे अंतराल तक बीएसएनएल मे काफी उतार–चढ़ाव के बाद दिनांक 22.10.2019 को भारत सरकार के मंत्रीपरिषद् ने बीएसएनएल के लिए पुनरूत्थान योजना का अनुमोदन किया। यह योजना भारतीय औद्योगिक प्रबंधन, अहमदाबाद के अनुशंसाओं पर आधारित था। हालांकि दूरसंचार विभाग ने आईआईएम के बहुत अनुशंसाओं को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें कर्मचारियों को लाभ था। पुनरूत्थान योजना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ अनुमोदित किया गया। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को बीएसएनएल वीआरएस 2019 के नाम से लागू किया गया। इसके लिए समयावधि 4 नवंबर 2019 से 3 दिसंबर 2019 तक रखा गया। कुल 78569 कर्मचारियों ने, जिसमें एक्जीक्युटिव एवं नान–एक्जीक्यूटिव शामिल हैं, वीआरएस के पक्ष में विकल्प दिया। कर्मचारियों को परोक्ष रूप से ऐसा करने को मजबूर किया गया। ज्ञातव्य है कि अध्यक्ष सह–प्रबंध–निदेशक (सीएमडी) ने दिनांक 25 अक्तूबर 2019 को एक धमकी भरा भाषण निगमित कार्यालय, नई दिल्ली के प्रांगण में दिया, जिससे उत्साहित होकर और (सीएमडी) के वक्तव्य का अनुसरण करते हुए सभी परिमंडलीय/बीए/एसएसए स्तर के अधिकारी ने आग में घी की आहूति डालते हुए कर्मचारियों को भयभीत किया तथा भ्रमित किया, जिसमें भारी संख्या में कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए विकल्प देते हुए अपने प्रिय संगठन बीएसएनएल को छोड़ने का मन बना लिया। शुरू के दौर में उच्च स्तरीय प्रबंधन के लोगों ने बार–बार यह दोहराया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का सभी प्रक्रिया सुचारू तरीके से पूरा किया जायेगा तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके सारे देयकों के भुगतान के बाद खुशी के साथ सम्मान सहित विदा किया जायेगा। उक्त आशय के विपरीत निगमित कार्यालय से सतर्कता प्रमाण पत्र देने के संबंध में दो प्रकार के पत्र जारी किये गये जिससे नीचे स्तर पर कर्मचारियों की कठिनाइयां बहुत बढ़ गयी। पेंशन उपादान एवं कम्यूटेशन के मामले में यूनियन द्वारा उठाये गये मुद्दों का स्पष्टीकरण नहीं जारी किया गया। जहां तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खुशी के माहौल में विदा करने की बात है उसका एक वीभत्स उदाहरण सामने आया कि प्रबंधन ने सेवानिवृत्ति के उपरांत उपहार के रूप में मिलने वाली 3001 रूपये की राशि को नहीं देने के लिए आदेश निर्गत किया गया, इतना नहीं उक्त आदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुष्पगुच्छ एवं अल्पाहार नहीं देने का भी लिखित आदेश निकाला गया। एनएफटीई ने इसे कर्मचारियों का अपमान मानते हुए अपना रंजिश दर्ज कराया। यूनियन द्वारा दो बार पत्र लिखने तथा निदेशक, कार्मिक के आश्वासन के बाद भी संशोधित आदेश जारी नहीं हुआ। प्रबंधन द्वारा यह कहा गया था कि 31 जनवरी 2020 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के दिसंबर 2019 तथा जनवरी 2020 के वेतन सहित उनके देयकों एवं कटौती का भुगतान 31 जनवरी 2020 से पूर्व कर दिया जायेगा। यह दुख ही नहीं अत्यंत पीड़ादायक है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन रहित विदाई दी गयी जिसका हम घोर निंदा करते हैं।

यह पुनरूत्थान योजना का एक हिस्से की पूर्णाहूति है, इसके उपरांत पुनरूत्थान के मामले में अन्य बिंदु जैसे 4जी स्पेक्ट्रम, लैंड मोनिटाईजेशन, गोल्डेन बांड आदि पर किसी प्रकार का कोई पारदर्शी कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। 1 फरवरी 2020 से सेवाओं का विस्तार एवं अनुरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है। आउटसोर्सिंग की नीति के बारे में परिपत्र जारी किये गये हैं परंतु सरजमीन पर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिससे अजीब दुर्गंध की अनुभूति हो रही है।

एनएफटीई ने दक्षता प्राप्त कर्मचारियों की सेवा अनुबंध पर या मानदेय देकर चालू रखने की सलाह बार–बार प्रबंधन को दिया परंतु प्रबंधन की ओर से कोई तर्जी नहीं दी गयी। सारे मूल्य के आंकलन से एक अंधेरे स्थिति का अनुमान हो

रहा है। ऐसा समझा जाता है कि अभी वर्तमान के परिपेक्ष्य में बीएसएनएल में समाहित कर्मचारियों से अधिक नये भर्ती वाले कर्मचारियों की संख्या अधिक होगी, जिसकी लंबी सेवा होगी और उनके लिए एक ठोस एवं आधारभूति प्रक्रिया की संरचना अप्रेक्षित हैं उन तमाम कर्मचारियों को गोलबंद एवं संगठित होकर अपने भविष्य की संरचना करने हेतु अग्रसर होना पड़ेगा। एनएफटीई ने कर्मचारियों की हिरावल दस्ता तथा सुरक्षा चक्र के रूप में कार्य किया है और आज भी हम सभी यूनियनों एवं एसोसिएशनों की एकता की प्रबल पक्षधर हैं। हम एनएफटीई की ओर से तमाम कर्मचारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके हित रक्षा के लिए सर्वदा अगली कतार में खड़े होंगे।